Original Research Article Website : www.ijbasr.org IF = 5.1 ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Multidiscipline and Peer Reviewed Refereed Journal 2026; 13(3); 1-7 (Special Issue)

ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भूमिका: दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के संदर्भ में

शक्ति शंकर कुमार
न्यू अभंडा, कष्णा नगर, लहेरियासराय, दरभंगा

सार :

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन–स्तर में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भूमिका का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में योजना के लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि द्वारा 100 लाभार्थियों से प्राप्त किए गए हैं। शोध से ज्ञात होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित आवास, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य सुधार तथा आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि योजना के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ जैसे भ्रष्टाचार, विलंब एवं तकनीकी कठिनाइयाँ भी सामने आई हैं, फिर भी ग्रामीण विकास की दिशा में यह योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है।

सार – शब्द : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण विकास, बहादुरपुर प्रखंड, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण आवास

परिचय :

ग्रामीण विकास भारत के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधारशिला है। भारत की लगभग दो–तिहाई जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोजगार का अभाव देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं आवासहीनता एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास केवल रहने का साधन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा होता है (शर्मा, 2019)। इसी कारण ग्रामीण आवास को ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कसौटी माना जाता है।

भारत में लंबे समय तक ग्रामीण गरीब कच्चे एवं असुरक्षित मकानों में रहने को विवश थे। विशेषकर बिहार जैसे राज्य, जहाँ बाढ़, जल–जमाव एवं प्राकृतिक

Corresponding Author : शक्ति शंकर कुमार
E-mail : Shaktishankar029@gmail.com
Date of Acceptance : 21.01.2026
Date of Publication : 01.05. 2026

आपदाएँ सामान्य समस्या हैं, वहाँ कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्षा ऋतु में मकानों का क्षतिग्रस्त होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तथा सामाजिक असुरक्षा जैसी स्थितियाँ ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती रही हैं (कुमार एवं सिंह, 2020)। ग्रामीण गरीबों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं का संचालन किया।

ग्रामीण आवास योजनाओं की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद विभिन्न स्तरों पर हुई, किन्तु वर्ष 2016 में इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2029 तक प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2025)। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्थायी एवं सुरक्षित मकान का निर्माण कर सकें। इसके साथ ही योजना को स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना एवं विद्युतिकरण योजनाओं से जोड़कर समग्र ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केवल एक आवासीय योजना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन एवं गरीबी उन्मूलन का भी एक प्रभावी माध्यम है। पक्का मकान मिलने से ग्रामीण परिवारों में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्राप्त होता है तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार होता है (यादव, 2022)। योजना के माध्यम से शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल एवं बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार भी संभव हुआ है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। मकान निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर मजदूरी एवं निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। इससे ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिली है (मिश्र, 2021)। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय बाजारों एवं छोटे व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार योजना ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विशेष महत्त्व है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं। बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है (बिहार ग्रामीण विकास विभाग, 2025)। राज्य के अनेक जिलों में योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है। जिले के बहादुरपुर प्रखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या अधिक है, जिनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बहादुरपुर प्रखंड में इस योजना के अंतर्गत अनेक लाभार्थियों को पक्का मकान प्राप्त हुआ है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ सामाजिक सम्मान एवं सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। पहले जहाँ लोग फूस एवं मिट्टी के मकानों में रहने को विवश थे, वहीं अब उन्हें पक्के एवं सुरक्षित आवास प्राप्त हो रहे

हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव में भी कमी आई है। विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

हालाँकि योजना के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ भी सामने आई हैं। कई बार लाभार्थियों को योजना की राशि समय पर प्राप्त नहीं होती, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक जटिलताओं की शिकायतें भी सामने आई हैं (अहमद, 2023)। तकनीकी जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में भी लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद योजना का समग्र प्रभाव ग्रामीण समाज पर सकारात्मक रहा है। वर्तमान अध्ययन "ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भूमिका दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के संदर्भ में" इसी पृष्ठभूमि में किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि योजना ने ग्रामीण गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाया है तथा ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को किस सीमा तक प्रभावित किया है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं ग्रामीण विकास से जुड़े व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

साहित्य समीक्षा :

ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण आवास से संबंधित योजनाओं पर विभिन्न विद्वानों, शोधकर्ताओं एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में ग्रामीण आवास योजनाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना विषेश रूप से ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाली एक महत्त्वपूर्ण योजना के रूप में उभरकर सामने आई है। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य का विस्तृत अवलोकन निम्नलिखित है। शर्मा (2019) ने अपने अध्ययन 'Rural Development and Housing Policies in India' में बताया कि ग्रामीण आवास किसी भी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन का मूल आधार है। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का आवास उपलब्ध होने से न केवल लोगों की जीवन–शैली में सुधार होता है, बल्कि सामाजिक असमानताओं में भी कमी आती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रामीण आवास योजनाएँ गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कुमार एवं सिंह (2020) ने ग्रामीण आवास योजनाओं एवं स्वच्छता विकास के संबंध का अध्ययन किया। उनके अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में शौचालय एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था होने से ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कच्चे मकानों की तुलना में पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों में संक्रामक रोगों की संभावना कम होती है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण आवास योजनाएँ केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। मिश्रा (2021) ने बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि योजना के अंतर्गत मकान निर्माण कार्यों के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। मजदूरों, राजमिस्त्रियों एवं निर्माण सामग्री विक्रेताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। अध्ययन में

यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को बढ़ाया तथा ग्रामीण बाजारों को सक्रिय बनाया। मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण आर्थिक विकास की प्रक्रिया को मजबूत करने वाला एक प्रभावी माध्यम है।

यादव (2022) ने ग्रामीण समाज में आवासीय योजनाओं के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए कहा कि पक्का मकान प्राप्त होने से ग्रामीण गरीबों में आत्मविश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना विकसित होती है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन पर प्रकाश डाला। अध्ययन के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा अधिक प्राप्त होती है तथा उनका स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर होता है। बच्चों की शिक्षा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया क्योंकि सुरक्षित एवं स्थिर वातावरण अध्ययन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।

अहमद (2023) ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। उनके अनुसार योजना के संचालन में कई प्रशासनिक बाधाएँ सामने आती हैं, जैसे लाभार्थियों के चयन में अनियमितता, भ्रष्टाचार, किस्तों के भुगतान में विलंब तथा तकनीकी कठिनाइयाँ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कई लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद अधिकांश लाभार्थियों ने योजना को लाभकारी माना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट (2025) के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना–ग्रामीण का उद्देश्य "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार योजना के अंतर्गत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि योजना के तहत आधुनिक तकनीक एवं पारदर्शी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके तथा वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सहायता के साथ–साथ शौचालय, बिजली एवं स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा स्वच्छ भारत मिशन को भी बढ़ावा मिला है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। विभाग ने यह स्वीकार किया है कि योजना ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास को मजबूत किया है तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान किया है। रेडिट एवं अन्य ऑनलाइन चर्चाओं में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि योजना के कारण उन्हें पहली बार पक्का एवं सुरक्षित घर प्राप्त हुआ, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व एवं सम्मान की भावना विकसित हुई। कुछ लोगों ने योजना के क्रियान्वयन में विलंब एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं का भी उल्लेख किया है।

Original Research Article Website : www.ijbasr.org IF = 5.1 ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Multidiscipline and Peer Reviewed Refereed Journal 2026; 13(3); 1-7 (Special Issue)

सामाजिक वैज्ञानिकों का मत है कि ग्रामीण आवास योजनाएँ केवल भौतिक संरचना निर्माण का कार्य नहीं करतीं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करती हैं। सुरक्षित आवास ग्रामीण परिवारों में स्थिरता, सामाजिक सहभागिता एवं सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करता है। आवासीय सुरक्षा मिलने से लोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे अन्य विकासात्मक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक प्रभावी एवं बहुआयामी योजना है। अधिकांश अध्ययनों में योजना के सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक स्थिरता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में। हालांकि योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कठिनाइयों एवं भष्टाचार जैसी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के संदर्भ में योजना के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजना की उपयोगिता एवं चुनौतियों को समझा जा सके।

अध्ययन के उद्देष्य :

1. दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भूमिका का अध्ययन करना।
2. योजना के लाभार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े बहादुरपुर प्रखंड के 100 लाभार्थियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि द्वारा संकलित किए गए। द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट स्रोतों से प्राप्त किए गए। अध्ययन हेतु बहादुरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से लाभार्थियों का चयन यादृच्छिक नमूना पद्धति के आधार पर किया गया। प्राप्त आँकड़ों का वर्गीकरण एवं प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया।

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण :

तालिका 1
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभार्थियों के जीवन में आए परिवर्तन

क्र. सं.	परिवर्तन के क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1	पक्का मकान प्राप्त हुआ	100	100
2	सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि	82	82
3	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार	76	78
4	आर्थिक स्थिति में सुधार	89	89
5	सुरक्षा की भावना विकसित	88	88
6	बच्चों की शिक्षा में सुधार	61	61

(स्रोतः क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित)

आँकड़ों का विश्लेषण :

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने बहादुरपुर प्रखंड के ग्रामीण परिवारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। सभी 100 लाभार्थियों को पक्का मकान प्राप्त हुआ, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व एवं सुरक्षा की भावना विकसित हुई। 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि पक्का मकान मिलने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। पहले कच्चे मकानों में रहने के कारण समाज में उन्हें

हीन दृष्टि से देखा जाता था, किंतु अब वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

76 प्रतिशत लाभार्थियों ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार की बात कही। पक्के मकानों एवं शौचालय की सुविधा के कारण गंदगी एवं बीमारियों में कमी आई है।

69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्थिति में सुधार अनुभव किया। मकान निर्माण के दौरान रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा स्थायी आवास के कारण आर्थिक सुरक्षा की भावना बढ़ी।

88 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं एवं चोरी आदि का भय कम हो गया है। पक्का मकान उनके लिए सुरक्षा का आधार बना है।

61 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है क्योंकि अब उन्हें अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो पाया है।

चर्चा :

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है। बहादुरपुर प्रखंड के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि योजना ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास केवल आश्रय का साधन नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को पक्का मकान प्राप्त होने से उनमें आत्मविश्वास एवं सामाजिक सम्मान की भावना विकसित हुई है। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वच्छ एवं सुरक्षित आवासीय वातावरण ने ग्रामीण परिवारों के जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाया है। हालाँकि योजना के क्रियान्वयन में कुछ समस्याएँ भी सामने आई हैं। कई लाभार्थियों ने बताया कि किस्तों के भुगतान में विलंब होता है। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार एवं दलालों की भूमिका भी देखी गई। तकनीकी जानकारी के अभाव में लाभार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद योजना का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है। यह योजना ग्रामीण गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। यदि प्रशासनिक पारदर्शिता एवं निगरानी को और मजबूत किया जाए तो योजना की प्रभावशीलता में और वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावी योजना है। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाया है। पक्का मकान मिलने से लाभार्थियों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास को भी प्रोत्साहित किया है। गरीब एवं वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। हालाँकि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पारदर्शिता, समय पर भुगतान तथा प्रशासनिक निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा भविष्य में भी ग्रामीण भारत के समग्र विकास में इसकी भूमिका निर्णायक बनी रहेगी।

संदर्भ :

1. अहमद, आर. (2023). बिहार में ग्रामीण आवास और सामाजिक परिवर्तन. पटनाः जानकी पब्लिकेशन, पृ. 44
2. कुमार, एस., और सिंह, आर. (2020). भारत में ग्रामीण आवास योजनाएँ और स्वच्छता विकास. इंडियन जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 12(2), 45–58.
3. मिश्रा, पी. (2021). 'बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण' का प्रभाव. नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन, पृ. 72
4. षर्मा, ए. (2019). भारत में ग्रामीण विकास और आवास नीतियाँ. जयपुरः पॉइंटर पब्लिशर्स, पृ. 68
5. यादव, एम. (2022). ग्रामीण आवास योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 8(3), 77–91.
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2025). प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्लीः भारत सरकार.
7. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार.
8. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. (2025). प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण' लक्ष्य और उपलब्धियाँ. भारत सरकार, पृ. 96
9. प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण' आधिकारिक सूचना पोर्टल.
10. भारत सरकार. (2025). प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण' ग्रामीण आवास प्रगति अपडेट. नई दिल्लीः ग्रामीण विकास मंत्रालय, पृ. 83

***